reservations expressed by the Agricultural Cost and Prices Commission over the norms followed to calculate support prices;

(b) if so, what are the main observations made in this regard; and

(c) by when the procurement price policy is likely to be revised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (c) As at present the procurement/ minimum support prices for Kharif crops of 1990-91, announced by the Government on 16-6-1990 will need revision only if the rise in input costs during the cropping season turns out to be higher than the anticipated rise.

The non-price recommendations contained in the Report of the Commission for Agricultural Costs and Prices for Kharif crops of 1990-91 are under consideration.

Recommendations of Bhanu Pratap Committee regarding Food Corporation of India

1999. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bhanu Pratap Committee has described the Food Corporation of India as a "luxuriating bureaucracy";

(b) if so, what is Government's reaction to the view that the Food Corporation of India is too large and wasteful;

(c) what steps are proposed to be taken to reduce the high management expenditure; and

(d) whether Government propose to bifurcate the Food Corporation of India?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR: (a) and (b) The Report of the Committee received on 30th July, 1990 is under examination.

(c) The Food Corporation of India has been implementing cost reduction plans since 1986-87 with a view to reducing its operational costs. During the years 1986-87 to 1989-90, the Corporation achieved savings of Rs. 667.65 crores. The FCI has taken number of steps to reduce the Transit and Storage shortages. As a result of these measures, the Transit and Storage shortages. have been reduced from 2.37 per cent in 1982-83 to 1.25 per cent in 1988-89 with reference to purchase + sales of foodgrains.

(d) There is no proposal to bifurcate the Food Corporation of India.

दिल्ली का द्वितीय मास्टर प्लान

2000. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए द्वितीय मास्ट प्लान तैयार हो गया है ; यदि हां, तो इस मास्टर प्लान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसका कार्यान्वयन कब से शुरू होने की संभावना है ;

(ख) संदर्भाधीन मास्टर प्लान के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और अलग-अलग मदों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या संदर्भाधीन मास्टर प्लान के लिए वित्तीय अनुमान तैयार करते समय, खर्च में होने वाली सामान्य वार्षिक वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 2001 तक

प्रक्षेपणों पर आधारित संसाधनों को सरकार पहले ही अनुमोदित कर चुकी हैं और दिल्ली की बृहद योजना (संदर्भ-2001), इसके लागू होने की तारीख अर्थात् 1 अगस्त, 1990 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. इसमें वर्ष 2001 तक 128 लाख जनसंख्या के प्रबन्ध के लिए विभिन्न शहरी क्रियाकलापों जैसे आवास, परिवहन, रोजगार केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, मनोरंजनात्मक क्षेत्रों आदि के लिए विकसित किए जाने वाले शहर एवं क्षेत्र के सुनियोजित विकास की व्यवस्था है ।

2. इस योजना में छोटे रिहायशी प्लाटों पर संवृद्धि आवास की संकल्पना को लागू किया गया है। जिससे निम्न आय वर्ग लाभान्वित होंगे ।

3. रेल ट्रांजिट सेवाओं सहित एक बहुरूपात्मक जन परिवहन प्रणाली एवं चार दिशाओं वाले महानगरीय यात्री टर्मिनलों, चार लदान परिसरों तथा पांच अन्तर्राजीय बस टर्मिनलों का भी प्रस्ताव किया जाता है ।

4. पहली बार मिश्रित भ–उपयोग और "अनौपचारिक क्षेत्र" की संकल्पना का प्रस्ताव किया गया है।

5. पहाड़ी और नदी के रूप में प्राकृतिक विरासत और—पर्यावरण का संरक्षण एवं विभिन्न स्तरों पर मनोरंजनात्मक तथा खेल-कूद के लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्रों के विकास का इस योजना में प्रस्ताव किया गया है ।

6. समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने और—अधिक बेहतर जीवन कोटि के लिए पर्यावरण तैयार करने के लिए भूमि को संरक्षित करने हेतु स्थानग्रस्तरों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है ।

7. उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए तथा ग्रामीण औद्योगिक सम्पदाओं एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी 11 ग्रामीण विकास केन्द्रों की भी इस योजना में पहचान की गई है ।

8. योजना में (क) सुव्यवस्थित विकास कोड और (ख) ससक्त प्रबोधन एकक की व्यवस्था की गई है ।

(ख) बृहद योजना एक अनिवार्यतः भू-उपयोग योजना है जिसमें नगर जीवन कोटि में सुधार करने का लक्ष्य एवं विकास प्राप्त करने के लिये उपयुक्त नीतियां तैयार करने हेतु नगर-आयोजना और विकास नीतियों पर बल दिया गया है। इसमें आयोजना मानदण्ड और विकास पद्धतियां भी निर्धारित की गई हैं जिनका स्वरूप व्यवस्थित है । इसमें विभिन्न योजनाओं के लिये वित्तीय नियतनों की व्यवस्था नहीं है । ये दिल्ली प्रशासन स्थानीय निकायों और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों/अभिकरणों द्वारा तैयार किये जाने हैं जिन्हें योजना के अनुसार ऐसा करना है और अपने-अपने बजटों में इसके लिये वित्तीय प्रावधान करने हैं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

Production of vegetables and fruits

2001. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the production of different fruits and vegetables, itemwise during the last 3 years in different States;

(a) what was their average price during the last 3 years;

(c) what is Government's plan to increase the production so that the prices can be maintained at lower level; and